AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Subject :- Non-settlement of pension cases of employees-present status for general information (updated on 28-03-2012.

Member (HR) had a meeting with the Secretary to Govt. of India, Ministry of Labour and Employment on 21.03.2012 regarding early settlement of pension claims in respect of AAI employees where Central Provident Fund Commissioner (CPFC) was also present.

In the meeting, it was mentioned that AAI is ready to pay the interest component and the payment of damages may be delinked from settling of pension claims of AAI employees. As advised by the Labour Secretary, a meeting between AAI & CPFC officials was held in the office of CPFC on 23.03.2012. In the said meeting, it was decided that the issue may be discussed again in a meeting of officials involving CPFC, RPFC, Delhi & AAI. The meeting was slated to be held on 23.03.2012(afternoon), however, due to some reasons, it was postponed by CPFC. Prior to it, Member (HR) vide his DO letter dated 21-03-2012 addressed to CPFC had informed CPFC that the levy of damages for pre-discovery period (01-04-1995 to 22-08-2007) in case of AAI does not appear to be in order in view of CPFC circulars dated 17-06-2004, 13-02-2009 and Hon'ble Kolkata High Court Judgement dated 22-12-2011in an identical case.

There appears to be some doubt in some quarters in CPFC as to the eligibility of AAI employees for pension on actual salary. The same has also been clarified vide Member (HR)'s DO letter dated 24-03-2012 quoting para 11(3) of Employees Pension Scheme, 1995 as to how AAI employees are eligible for pension on actual salary basis and it was also reminded that RPFC-1 Delhi have already cleared pension claims of 136 beneficiaries of AAI who had opted for pension on actual salary basis.

In the meanwhile, CHQ officials alongwith the RHQ, ER officials have also attended a hearing in the Dist. Consumer Disputes Redressal Forum Kolkata on 26-03-2012 on the complaint filed by one of AAI retired employees. The Hon'ble Court was apprised that the Airports Authority of India had already submitted the pension claim with all requisite documents of the said official to RPFC-1 Delhi and payment towards pension contribution has also been made to RPFC-1, Delhi. The Hon'ble Court was further informed that it is for the RPFC to settle and disburse the pension of the said employee. The Hon'ble Court agreed with the argument of AAI and sought reasons from RPFC for not settling the pension claims of the said employee. However, the RPFC have sought time to furnish reply and the **next date of hearing** has been fixed on **13.04.2012.**

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Subject: Non-settlement of pension cases of employees - present status for general information (updated on 09th March, 2012)

- The matter has since been taken up with Regional Provident Fund Commissioner-I and Central Provident Fund Commissioner on 05/03/2012 & 09/03/2012 inviting their attention to their legal obligation under the provision as contained in Para 16(a) of the Employees Pension Scheme, 1995 and requesting them to de-link the settlement of pension claims and AAI's obligations as non-settlement of pension claims is causing undue hardship to the beneficiaries.

*****

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

विषय: कर्मचारियों के पेंशन मामलों का समाधान न होना - सामान्य जानकारी हेतु वर्तमान स्थिति ।

- 16.1.2007 को पी एफ अधिनियम के तहत भा.वि.प्रा. के कर्मचारियों के लिए सी पी एफ ओ को एक आवेदन किया गया था ।
- 17.8.2007 को अपर पी एफ आयुक्त, नॉर्थ जोन, नई दिल्ली ने 1.4.1995, अर्थात् भा.वि.प्रा. के गठन की तारीख से प्रभावी भा.वि.प्रा. के कर्मचारियों को शामिल करने के लिए एक आदेश पारित किया ।
- 22.8.2007 को भा.वि.प्रा. को ई पी एफ ओ द्वारा कोड नं0 डी एल/36478 निर्धारित किया गया ।
- 08.10.2007 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली (उत्तरी) के माध्यम से सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को अपने ही संगठन में (इन हाउस) भविष्य निधि को जारी रखने के लिए छूट मांगने संबंधी एक आवेदन किया गया था ।
- 30.4.2010 को आर पी एफ सी, दिल्ली द्वारा भा.वि.प्रा. को अपने संगठन में (इन हाउस) भविष्य निधि को जारी रखने के लिए धारा 17(2) के साथ पठनीय ई पी एफ अधिनियम, 1952 के पैरा 27(ए) के तहत रियायत/ छूट अनुमोदित की गई ।
- जुलाई, 2011 को आर पी एफ सी, दिल्ली द्वारा 157 दावों का निपटारा किया गया, जिसमें से उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 80 पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ) दिल्ली से आने वाले कार्मिकों को जारी किए गए थे तथा देश के अन्य भागों से आने वाले शेष 77 कार्मिकों के लिए पेंशन स्वीकृति आदेश भी जारी किए गए । इस श्रेणी के कार्मिकों को अर्थात् दिल्ली के बाहर से आने वाले कार्मिकों के लिए पेंशन भुगतान आदेश उन कार्मिकों की लोकेलिटी के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी किए जाएंगे ।

- हालांकि चेन्नई व गुडगाँव ने पेंशन भुगतान आदेश जारी कर दिए हैं। कोलकाता एवं मुंबई स्थित आर पी एफ सी ने उन कार्मिकों से संबंधित पेंशन भुगतान आदेश जारी नहीं किए है जिन्होंने वास्तविक वेतन पर पेंशन के विकल्प को चुना है तथा इन्होंने आर पी एफ सी, दिल्ली से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं।
- तदनुसार, आर पी एफ सी, दिल्ली ने वास्तविक वेतन पर पेंशन के दावों का निपटारा रोक दिया है।
- भा.वि.प्रा. को ई पी एफ योजना, 1952 के अनुच्छेद 26(ख) के तहत वास्तविक वेतन पर अंशदान के लिए कार्योत्तर अनुमोदन हेतु आवेदन करने का सुझाव दिया गया था। इस सुझाव का तत्काल पालन किया गया।
- दिसम्बर, 2011 के प्रथम सप्ताह के दौरान अपर भविष्य निधि आयुक्त (दिल्ली उत्तरी) ने यह मामला केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को विचारार्थ भेज दिया।
- केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने 30.12.2011 को एक बैठक बुलाई जिसमें सी पी एफ सी, आर पी एफ सी, दिल्ली तथा भा.वि.प्रा. के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
- सी पी एफ सी कार्यालय का विचार है कि वित्त तथा अनुपालन मुद्दों को सुलझाना अभी बाकी है और जब तक कि दंड क्षतियों आदि की पिछली संचित उगाही के हस्तांतरण से संबंधित मुद्दे आर पी एफ सी - । दिल्ली उत्तरी द्वारा नहीं सुलझाए जाते, तब तक मुख्यालय का पेंशन प्रभाग इन मुद्दों पर आगे विचार करने की स्थिति में नहीं होगा।
- 25.1.2011 को हुई बैठक में आर पी एफ सी, दिल्ली ने इस बात पर बल दिया कि भा.वि.प्रा. को अधिनियम के अनुरूप ब्याज तथा क्षतियों का भुगतान करना है व क्षतियों की उगाही की गणना दिनांक 1.4.1995 से की जाएगी।

- भा.वि.प्रा. के परामर्शदाता ने सलाह दी है कि भा.वि.प्रा. को सितम्बर, 1997 से 12% की दर से केवल साधारण ब्याज का भुगतान करना है । क्षतियों के संबंध में उन्होंने सुझाव दिया है कि यह केवल दिनांक 22.8.2007 से लागू होगा जोकि आर पी एफ सी, दिल्ली द्वारा प्रदत्त कवरेज की तिथि है और 1.4.1995 से 21.7.2007 के प्री डिस्कवरी अवधि पर यह उगाही लागू नहीं होगी ।
- इसी प्रकार के एक मामले में, दिनांक 22.12.2011 को माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि दिनांक 16.6.2004 के सी पी एफ सी परिपत्र द्वारा प्रदत्त क्षतियों के भुगतान में छूट का लाभ तथा दिनांक 16.2.2009 से पूर्ववर्ती परिपत्र को खारिज करने वाला उत्तरवर्ती परिपत्र पहले प्रदत्त लाभ वापिस नहीं ले सकता । अन्य शब्दों में, 2007 से पूर्व प्री डिस्कवरी अवधि पर क्षतियां लागू नहीं होगी ।
- भा.वि.प्रा. के दिनांक 2.2.2012 के पत्र के उत्तर में, जिसमें मामले के शीघ्र निपटान हेतु बैठक करने का अनुरोध किया गया था, आर पी एफ सी (पेंशन), नई दिल्ली ने अपने दिनांक 14.2.2012 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि अपर सी पी एफ सी (डी एल व यू के) को निदेश दिए गए हैं कि वे इस मामले में तुरन्त कार्रवाई करें बशर्ते कुछ 'विशिष्ट' शर्तें पूरी हों ।
- तदनुसार, सहायक भविष्य निधि आयुक्त (क्षतियां) ने अपने दिनांक 21.2.2012 के पत्र के माध्यम से भा.वि.प्रा. से तुरन्त रू. 3,36,69,88,693 (ब्याज 1,22,79,12,660 + क्षतियां रू. 2,13,90,76,033) का भुगतान करने के लिए कहा है ।
- भा.वि.प्रा. इस मामले में आगे की कार्रवाई हेतु कानूनी परामर्श ले रही है ताकि वह अपने कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान के मुद्दे को भा.वि.प्रा. द्वारा भविष्य निधि प्राधिकारियों को देय बकाया राशि के मुद्दे से अलग कर सके ।

******

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Subject:- Non settlement of pension cases of employees — present status for general information.

- On 16.1.2007, an application was made to CPFO to cover employees of AAI under the PF Act.

- On 17.8.2007, The Additional PF Commissioner, North Zone, New Delhi passed an order for coverage to the employees of AAI with effect from 1.4.1995 i.e. the date of formation of AAI.

- On 22.8.2007, AAI allotted Code No. DL/36478 by EPFO.

- On 8.10.2007, an Application was made to the Secretary, Ministry of Labour and Employment through Regional PF Commissioner, Delhi (N) seeking exemption to maintain Provident Fund in house.

- On 30.4.2010, RPFC, Delhi approved relaxation/exemption under Para 27(A) of EPF Act, 1952 read with Section 17(2) for AAI to maintain Provident Fund in house.

- As of July, 2011, 157 claims have been settled by RPFC, Delhi, out of which 80 Pension Payment Orders (PPOs) were directly issued by them for the officials hailing from Delhi and pension sanction order for remaining 77 officials hailing from other parts of the country were also issued. For this category of officials i.e. hailing from outside Delhi, PPOs are to be issued by the concerned Regional Provident Fund Commissioner according to the locality for such officials.

- While Chennai and Gurgaon have issued PPOs, Kolkata and Mumbai RPFCs have not issued the PPOs in respect of officials who have opted for the pension on actual salary and have sought certain clarifications from RPFC, Delhi.

- Subsequently, the RPFC, Delhi have stopped settling the pension claims on actual salary

- AAI had been advised to apply for *ex post facto* approval for contribution on actual salary under para 26 (b) of EPF Scheme, 1952. The same was compiled forthwith.

- Additional Provident Fund Commissioner (Delhi North) referred the case to Central Provident Fund Commissioner during the first week of December, 2011.

- The Central Provident Fund Commissioner convened a meeting on 30.12.2011 wherein the senior officials from CPFC, RPFC, Delhi and AAI were present.

- CPFC Office is of the opinion of *that financial and compliance issues are yet to be resolved and unless issues relating to transfer of past accumulations levy of penal damages etc. are taken care of by RPFC-I Delhi North, Pension Division in Head Office* ***shall not be in a position to examine the issues any further***."

- In a meeting held on 25.1.2011 RPFC, Delhi, emphasized that AAI is required to pay interest and damages as per ACT and recovery of the damages will be calculated with effect from 1.4.1995.

- AAI's Consultant has advised that AAI needs to pay only the simple interest @ 12% with effect from September, 1997. Regarding damages, he has advised that the same will be applicable only from 22.8.2007 i.e. the date of coverage given by RPFC, Delhi and not for the pre-discovery period i.e. 1.4.1995 to 21.7.2007.

- In a similar case the Hon'ble Kolkata High Court has delivered a judgment on 22.12.2011 stating that benefit of exemption from paying damages as was conferred by CPFC Circular dated 16.6.2004 and the subsequent Circular withdrawing the earlier Circular prospectively with effect from 16.2.2009 cannot take away the benefit which was granted earlier. In other words, the damages will not be applicable for the pre-discovery period prior to 2007.

- In response to AAI's letter dated 2.2.2012 requesting for a meeting for early settlement of issue, RPFC(Pension), New Delhi has, vide his letter dated 14.2.2012, informed that Additional CPFC (DL & UK) has been given instructions to take necessary action in the matter subject to fulfillment of certain obligations.

- Subsequently, Assistant PF Commissioner (Damages) has, vide his letter dated 21.2.2012, asked AAI to pay immediately an amount of Rs.3,36,69,88,693(Interest1,22,79,12,660+Damages Rs.2,13,90,76,033).

- AAI is taking legal opinion as to the further course of action in the matter so as to delink the issue of payment of pension to its employees from dues to be paid by AAI to PF authorities.

*****